



प्रेस समाचार

सालियन, चाणक्यपुरी, नई दिल्ली 110021 फ़ोन: 011-24198000 एक्सटेंशन: 8827 फैक्स: 011-24198817
ईमेल: mpl@pd.state.gov इंटरनेट वेबसाइट: <http://usembassy.state.gov/delhi.html>

26 अप्रैल, 2006

अमेरिकी दूतावास के सहयोग से बौद्धिक संपदा अधिकार प्रवर्तन हेतु प्रशिक्षण कार्यशाला

नई दिल्ली -- आज 'विश्व बौद्धिक संपदा दिवस' के अवसर पर अमेरिकी दूतावास, भारत सरकार तथा भारतीय उद्योग परिसंघ के साथ मिलकर 26 अप्रैल से 11 मई, 2006 तक दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता में बौद्धिक संपदा अधिकार (आईपीआर) प्रवर्तन हेतु प्रशिक्षण कार्यशालाओं का आयोजन कर रहा है।

इस कार्यक्रम का उद्देश्य आईपीआर प्रवर्तन के लिए अपनाई गई पद्धतियों के अमेरिकी दृष्टिकोण से अवगत कराना तथा इन अधिकारों के प्रभावी प्रवर्तन के लिए सार्वजनिक व निजी क्षेत्रों की भागीदारी हेतु आधार तैयार करना है। अमेरिकी तकनीकी विशेषज्ञ उपरोक्त शहरों में जाएंगे तथा नकलरोधी कार्यक्रमों तथा इन प्रक्रियाओं में सरकारी एजेंसियों की भूमिका पर विचार करेंगे। तेजी से बढ़ते भारत-अमेरिका के आर्थिक रिश्तों में भारत में उन्नत आईपीआर सुरक्षा अमेरिका की पहली प्राथमिकता है।

आज यहां उद्घाटन समारोह में बोलते हुए अमेरिकी दूतावास के प्रभारी राजदूत रॉबर्ट ओ. ब्लेक ने कहा, "हमारी दोनों ज्ञान आधारित अर्थव्यवस्थाओं के बीच संयुक्त अनुसंधान व विकास के लिए मजबूत आईपीआर सुरक्षा असीम संभावनाओं का आधार है।" श्री ब्लेक ने यह भी घोषणा की कि अमेरिकी पेटेंट तथा ट्रेडमार्क ऑफिस नई दिल्ली आईपीआर अटैचे की नियुक्ति करेगा, जिसका कार्य विशेष रूप से बौद्धिक संपदा अधिकारों के मुद्रों पर भारत-अमेरिकी सहयोग को और बढ़ाना होगा।

भारत-अमेरिकी सेमिनार तथा कार्यशाला में प्रभावी आईपीआर प्रवर्तन जैसे कानूनी तथा प्रक्रियात्मक सुधारों के लिए भारत संबंधी महत्वपूर्ण मुद्रों की पहचान की जाएगी। इस समय भारत सरकार जिसका समस्या का सामना कर रही है वह यह सुनिश्चित करना है कि राष्ट्रीय कानून तथा प्रवर्तन में सुरक्षा के अंतर्राष्ट्रीय मानदंडों पर समुचित ध्यान दिया गया है, जिसके लिए डब्ल्यूटीओ के सदस्य के रूप में भारत प्रतिबद्ध है तथा यह सुनिश्चित करना है कि बौद्धिक संपदा अधिकारों के व्यापार संबंधी पहलुओं के समझौते के प्रावधानों का पालन किया गया है।

सेमिनार तथा प्रशिक्षण कार्यक्रम नई दिल्ली में 26-28 अप्रैल को ग्रैंड होटल () में शुरू होगा जहां भारत की केंद्र सरकार के नीति-निर्माता भाग लेंगे तथा आईपीआर प्रवर्तन तथा इसके असली लाभों के बारे में भारत-अमेरिकी परिग्रेश्य पर विचार-विमर्श करेंगे।
